tuted any committee to set up and encourage industries in the tribal areas of Gujarat State;

(b) if so, the steps taken by Government to bring industrial revolution in the tribal and rural areas of this region and to provide opportunities of self-employment to the unemployed youth there; and

(c) the funds proposed to be allocated for this purpose by Government in the next financial year, 1995-96?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) The Khadi & Village Industries Commission has taken number of steps to improve the production and thereby employment in Khadi & Village Industries in Gujarat. KVIC has a proposal to implement Special Employment programme in 125 Blocks in the country. Under this programme the following blocks have been selected in Gujarat. The employment generation in each block is expected to be 1000.

Districts	*Blocks*
1. Valsad	Darampur
2. Surat	Palsana
3. Rajkot	Jasdan
4. Sabarkantha	Meghraj
5. Bhavnagar	Savarkundla
6. Surendranagar	Desada.

Besides the above, as per recommendation of the High Power Committee, KVIC has also decided to implement Special Programme in 50 backward districts of the country. In Gujarat, the Special Employment Programme is implemented in Banaskantha and Panchmahal districts. The employment generation in each district under this programme is estimated to be 1000 persons.

(c) KVIC is yet to earmark funds for these activities for 1995-96 for Gujarat.

लघु उद्योगों में निवेश की सीमा में वृद्धि

4781. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के लघु उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा 1.5 करोड़ रुपये करने तथा बड़े और मध्यम उद्योगों की लघु उद्योगों में भागीदारी 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक करने के निर्णय से लघु उद्योग की इकाइयों पर होने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि लघु उद्योगों में वर्तमान प्रचलित व्यवस्था श्रम प्रधान होने के कारण तुलनात्मक दृष्टि से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा लघु उद्योगों मे पूंजी प्रधान व्यवस्था स्थापित होने से कौन से अतिरिक्त लाभ होने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) निवेश और लघु उद्योगों में इक्विटी भागीदारी की अधिकतम सीमा बढ़ाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किन्तु ऐसे मामलों में कोई निर्णय लेने से पहले सभी सम्बद्ध बातों पर विचार किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

लघु उद्योग एककों में उत्पादन और निर्यात

4782. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या प्रधान मंत्री 16 मार्च, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 680 के दिए गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग देश के कुल, उत्पादन में 40 प्रतिशत का योगदान करते है तथा देश के कुल निर्यात में 35 प्रतिशत योगदान इनका होता है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ग) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल कितने लघु उद्योग एकक कार्यरत हो जाने का अनुमान है और सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में यह संख्या कितनी अधिक होगी?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है किन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कुल 20.82 लाख मौजूद एककों की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 1992-93 और 1993-94 के दौरान लघु औद्योगिक एककों की संख्या क्रमशः 22.35 लाख और 23.84 लाख थी।

MoU signed for setting up paper and sugar project in Punjab

4783. SHRI IQBAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have signed any Memorandum of Understanding to set up a project of producing paper and sugar in the State of Punjab during the last two years;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken by Government in this respect?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OR INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सुविधाएं

4784. **श्री इकबाल सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और नयी उदारीकरण नीति के अंतर्गत विदेशी कंपनियों से प्रतिद्वन्दिता करने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करने की कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र की भूमिका को सरकार ने स्वीकार किया है। अतः इन उद्योगों के विकास को औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिकता मिल रही है और इस क्षेत्र को सहायता उपलब्ध कराना सरकार की औद्योगिक नीति की एक मुख्य विशेषता रही है।

सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जिनमें संस्थागत सहायता और रियायती वित्त जैसे प्रोत्साहन व रियायतें, उत्पाद शुल्क के लाभ, अनन्य उत्पादन के लिए मदों का आरक्षण, लघु एककों से खरीददारी के लिए मदों का आरक्षण, तकनीकि परामर्श सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं, सामान्य सुविधा सेवाएं और आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं। राज्य सरकारें भी इस क्षेत्र को सुविधाएं और प्रोत्साहन देती हैं।

(ख) से (ग) लघु क्षेत्र में अनन्य विनिर्माण के लिए उत्पादों का आरक्षण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने और उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए सरकार की नीति जारी है। बड़े और मझौले एककों द्वारा आरक्षित मदों का विनिर्माण करने के लिए 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व और स्वदेशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा लघु औद्योगिक क्षेत्र की इक्विटी में 24 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी न करने की अनुमति देने से सम्बन्धित प्रावधानों का उद्देश्य लघु क्षेत्रों के हितों की रक्षा करना है।

Off loading of PSU shares

4785. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report published in the 'Times of India' of January 2, 1995 under the caption, "PSU blue chips find way to grey market";

(b) If so, what are the facts and necessary details in this regard;

(c) what were the recommendations of the Jankiraman Committee which looked